

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 85/19
(आरसीएमएस संख्या 2019/00128)

निर्णय दिनांक: 23-12-2019

1. चुन्नीलाल दत्तक पुत्र रामीबाई जाति जाट निवासी सादुल कॉलोनी, बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 25-11-1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट
श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—



अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 25-11-1987 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अपील आधिका-
अपील आधिका-
बीकानेर
आदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के खारिजी प्रार्थना पत्र को जरिये बस्ता संख्या 256 पैड संख्या 1572 कम संख्या 248 मिसल संख्या 91/98 आयुक्त उपनिवेशन एवं अभिलेखागार में जमा करवा दी गई। कालान्तर में अपीलांत की पत्रावली को विडिंग कमेटी द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 1954 की धारा 137 के अनुसार विडिंग करने की अवधि अर्थात् 12 वर्ष उपरान्त अपीलांत की पत्रावली को विनिष्ट कर दिया गया। अपीलांत एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांत आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांत से पुनः दस्तावेज लेकर नई पत्रावली संयोजित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।



अभिभाषक अपीलांत ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-11-1987 के विरुद्ध अपील 26-04-2019 को पेश की है। जो करीब 32 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अतः अपीलांत अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-11-1987 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 26-04-2019 को पेश की गई है। अपीलांत द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 1987 में आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् अपीलांत द्वारा आगामी 32 वर्षों में अपने प्रार्थना पत्र पर भूमिहीन आवंटन कराने हेतु किसी प्रकार की कोई चाराजोई नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में अपीलांत के प्रार्थना पत्र को


अधीनस्थ अपील अधिकारी
बीकानेर

विडिंग कमेटी के निर्णय के अनुसरण में विनिष्ट किया जा चुका है। अपीलांट स्वयं इतनी लम्बी अवधि तक अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। न्याय का भी यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25-11-1987 बहाल रखा जाता है।



9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23-12-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजस्थान अपील अदालत)
राजस्थान अपील अदालत अधिकारी
बीकानेर

